



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2019/पौष 25, 1940
No. 24]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2019/PAUSHA 25, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2019

मामला सं. एनएसआर- 07/2018

(न्यू शिपर समीक्षा)

विषय - इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और सउदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल" पर लागू पाटनरोधी शुल्क के मामले में पीटी. एनर्जी सेजहतेरा मास (उत्पादक) और सिनरमाससेप्सा पीटीई लि. (निर्यातक) के लिए अलग पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अधीन न्यू शिपर समीक्षा की शुरूआत।

सं. 7/38/2018-डीजीटीआर.—पीटी. एनर्जी सेजहतेरा मास (उत्पादक), इंडोनेशिया और सै. सिनरमाससेप्सा पीटीई लि. (निर्यातक/व्यापारी), सिंगापुर (जिन्हें आगे "याचिकाकर्ता" कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और सउदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के मामले में उनके लिए अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण को अनुरोध किया गया है। उक्त शुल्क की सिफारिश अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं 14/51/2016-डीजीएडी दिनांक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा की गई थी और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 28/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 25 मई, 2018 द्वारा

लगाया गया और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

शामिल उत्पादक/निर्यातक

1. वर्तमान जाँच पीटी. एनर्जी सेजहतेरा मास (उत्पादक), इंडोनेशिया और मै. सिनरमाससेप्सा पीटीई लि. (निर्यातक/व्यापारी), सिंगापुर द्वारा "सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल" (अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं 14/51/2016-डीजीएडी दिनांक 23 अप्रैल, 2018 में विचाराधीन उत्पाद के अधीन यथा-वर्णित) के प्रस्तावित निर्यातों से संबंधित है। प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार है।

नये उत्पादक/निर्यातक के संबंध में समीक्षा की शुरुआत

2. पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 में निम्नानुसार उल्लेख है :

22. ऐसे निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन जिनकी मूल रूप से जाँच नहीं की गई थी -(1) यदि किसी उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित निर्यातक देश के किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिसने जाँच की अवधि के दौरान भारत को उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया है, के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवधिक समीक्षा करेंगे, बशर्ते ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह सिद्ध करते हैं कि वे निर्यातक देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक से सम्बद्ध नहीं हैं, जिन पर उस उत्पाद हेतु पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार इस नियम के उप-नियम (1) में यथा-संदर्भित निर्यातकों अथवा उत्पादकों से किए गए आयातों पर जाँच अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण नहीं करेगी :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अनंतिम आकलन करे और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी संस्तुति करते हों तो आयातक से गारंटी प्राप्त करे और यदि ऐसी समीक्षा की परिणति ऐसे उत्पादों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन के निर्धारण में होती हो, तो ऐसे मामलों में वह समीक्षा की शुरुआत की तारीख से, भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क अधिरोपित करेगी।"

इन पाटनरोधी नियमों में प्राधिकारी के लिए जाँच के अधीन निर्यातक देश में किसी निर्यातक या उत्पाद के लिए पाटन का अलग मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ समीक्षा की शुरुआत करना अपेक्षित है जिसने पूर्ववर्ती जाँच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है और यह कि याचिकाकर्ता निर्यातक देश में ऐसे किसी भी निर्यातक अथवा उत्पादक से संबंधित नहीं हैं, जिनके संबंधित उत्पाद पर पाटन-रोधी शुल्क लगता है।

याचिकाकर्ताओं ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अधीन यथा-अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई है। प्राधिकारी, प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट होते हुए कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अधीन यथा-विहित शर्तें पूरी होती हैं, एतद्वारा अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं 14/51/2016-डीजीएडी दिनांक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा की गई सिफारिश और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 28/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 25 मई, 2018 द्वारा लगाये गए और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 25 सितम्बर, 2018 द्वारा बाद में संशोधित किए गए के अनुसरण में इंडोनेशिया, मलेशिया, और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल" के आयातों पर लगाये गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में उनके अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए न्यू शिपर समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

3. प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 28/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 25 मई, 2018 और बाद में सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 48/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 25

सितम्बर, 2018 द्वारा संशोधित को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए संबद्ध वस्तु के सभी निर्यातों के संबंध में इस समीक्षा के पूरे होने तक अनंतिम आकलन करने की सिफारिश करते हैं।

जॉच अवधि

4. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जॉच की अवधि 1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की है।

सूचना प्रस्तुत करना :

5. ज्ञात हितबद्ध पक्षों को विहित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और

निर्दिष्ट प्राधिकारी,

व्यापार उपचार महानिदेशालय,

वाणिज्य विभाग,

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

भारत सरकार,

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

6. इस समीक्षा से संबंधित समस्त सूचना जॉच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों से पहले-पहले उक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

7. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

8. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ और अगोपनीय पाठ की दो-दो (2-2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

9. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

10. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

11. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को

सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

12. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

13. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

14. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2019

Case No. NSR-07/2018

(New Shipper Review)

Subject:—Initiation of New Shipper Review under Rule 22 of the Anti-dumping Rules for determination of individual dumping margin for PT. Energi Sejahtera Mas (Producer) and Sinarmas Cepsa Pte Ltd. (Exporter) in the case of Anti-dumping duty imposed on “Saturated Fatty Alcohols” originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia.

No. 7/38/2018-DGTR.—PT. Energi Sejahtera Mas (Producer), Indonesia and M/s. Sinarmas Cepsa Pte Ltd. (Exporter/Trader), Singapore (hereinafter referred to as the “Petitioners”), have filed an application in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the “Act”) as amended from time to time and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “AD Rules”) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) requesting for determination of their individual dumping margin in the matter of anti-dumping duties levied on imports of “Saturated Fatty Alcohols” originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia. The said duties were recommended vide Final Findings Notification No. 14/51/2016-DGAD dated 23 April, 2018 and levied vide Customs Notification No. 28/2018-Customs (ADD) dated 25 May, 2018 and amended later through Customs Notification No. 48/2018-Customs (ADD) dated 25th September, 2018.

PRODUCER/EXPORTER INVOLVED

1. The present investigation relates to proposed exports by PT. Energi Sejahtera Mas (Producer), Indonesia and M/s. Sinarmas Cepsa Pte Ltd (Exporter/Trader), Singapore (hereinafter referred to as the “Petitioners”) of “Saturated Fatty Alcohols” (as described under Product Under Consideration in Final Findings No. 14/51/2016-DGAD dated 23 April, 2018). The application filed by the petitioners before the Authority is in accordance with the Act and the AD Rules.

INITIATION OF REVIEW IN RESPECT OF NEW PRODUCER / EXPORTER

2. Rule 22 of Anti-Dumping Rules states as under:

22. Margin of Dumping, for exporters not originally investigated - (1) “If a product is subject to anti-dumping duties, the designated authority shall carry out a periodical review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to India during the period of investigation, provided that these exporters or producers show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product.”

(2) The Central Government shall not levy anti-dumping duties under sub-section (1) of section 9A of the Act on imports from such exporters or producers during the period of review as referred to in sub-rule (1) of this rule:

Provided that the Central Government may resort to provisional assessment and may ask a guarantee from the importer if the designated authority so recommends and if such a review results in a determination of dumping in respect of such products or exporters, it may levy duty in such cases retrospectively from the date of the initiation of the review.”

These AD Rules require the Authority to initiate a review for the purpose of determining individual margin of dumping for any exporter or producer in the exporting subject country in question who has not exported the subject goods to India during the period of investigation of the earlier investigation in case the petitioner/s is/are not related to any of the exporters and producers in the exporting country who are subjected to the anti-dumping duty.

The Petitioners have provided necessary information as required under Rule 22 of AD Rules. The Authority, having been *prima facie* satisfied that the conditions as prescribed under Rule 22 of AD Rules are met with, hereby initiates a New Shipper Review investigation for determination of the individual dumping margin in relation to the anti-dumping duties levied on dumped imports of “**Saturated Fatty Alcohols**” **originating in or exported from Indonesia, Malaysia and Thailand** in pursuance of the recommendations made by the Authority vide No. 14/51/2016-DGAD dated 23 April, 2018 and levied vide Customs Notification No. 28/2018-Customs (ADD) dated 25 May, 2018 and amended later through Customs Notification No. 48/2018-Customs (ADD) dated 25 September, 2018.

3. The Authority also recommends provisional assessment on all exports of the subject goods made by the Petitioners till this review is completed, in accordance with Rule 22 of the AD Rules and having regard to Customs Notification No. 28/2018 dated 25 May, 2018 (ADD) and amended later through Customs Notifications No. 48/2018 (ADD) dated 25 September, 2018.

PERIOD OF INVESTIGATION:

4. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st January, 2018 to 31 December, 2018.

SUBMISSION OF INFORMATION:

5. The known interested parties are being informed separately to enable them to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the

Designated Authority,
Directorate General of Trade Remedies,
Department of Commerce,
Ministry of Commerce and Industry,
Government of India,

4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi -110001.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation to the above Authority in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

TIME LIMIT:

6. All information relating to this review should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than forty days from the date of initiation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available before the Authority in accordance with the AD Rules.

SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS.

7. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire’s response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page.

8. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non- confidential version must be submitted.

9. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

10. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary, a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Designated Authority.

11. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

12. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Designated Authority. The Designated Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE:

13. In terms of Rule 6(7) of Anti-Dumping Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

14. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Director General